राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्र

सच दिखाने का जज़्बा

Title CodeUPHIN : 49375

पूर्वांचल युग

www.purvanchalyug.in

वर्ष 01, अंक 10 महाराजगंज से प्रकाशित, गुरूवार, 27 जनवरी 2022 पेज : 12 मूल्य : रू02/-

शाहरुख खान के साथ.....पेज (8)

मुफ्त उपहार बांटने की खायत को बढ़ावा देने वाले दलों के खिलाफ याचिका

एस सी ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

(एजेन्सी)

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पूरा मामला एक याचिका से जुड़ा है जिसमें चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन मुफ्त का वादा करने या वितरित करने वाले दलों की मान्यता को रद्द किया जाए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि यह निस्संदेह एक गंभीर का मुद्दा है। हम जानना चाहते हैं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। निरूसंदेह यह एक गंभीर मुद्दा है। मुफ्त बजट नियमित बजट से परे है, भले ही यह एक भ्रष्ट प्रथा नहीं है, लेकिन कभी–कभी जैसा कि एससी द्वारा देखा गया है कि यह कुछ पार्टियों आदि के लिए समान अवसर नहीं है। बेंच ने सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का भी उल्लेख किया, जहां कोर्ट ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को प्रतिनिधित्व की धारा 123 के तहत श्भ्रष्ट अभ्यासश के

रूप में नहीं माना जा सकता है। लोक अधिनियम, 1951 ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए राजनीतिक दलों के परामर्श से चुनाव घोषणापत्र की सामग्री पर दिशानिर्देश तैयार करने और इसे आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में शामिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए और दिशा–निर्देशों के साथ–साथ कुछ मंजूरी भी जारी करने की जरूरत है। सिंह ने कहा कि कृपया देखें कि आखिरकार किसका पैसा देने का वादा किया गया है? यह लोगों का पैसा है। कुछ राज्यों पर प्रति व्यक्ति 3 लाख से अधिक का बोझ है, और अभी भी मुफ्त की पेशकश की जा रही है। कोर्ट ने उन्हें दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन बिना किसी के दिशानिर्देश पेशकश किए जा रहे हैं।

समस्त जनपद व देश वासियों को (26 जनवरी) गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विकास बिल्डिंग मैटेरियल

समस्त जनपद व देश वासियों को (26 जनवरी) गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अबरार खान
पूर्व प्रधान
जगदीशपुर अमेठी ग्राम सभा कोयलारा मुबारकपुर

समस्त जनपद व देश वासियों को (26 जनवरी) गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विमलेश सरोज

जगदीशपुर अमेठी – विधानसभा जगदीशपुर 184 से संभावित प्रत्याशी एवं सपा नेत्री

समस्त जनपद व देश वासियों को (26 जनवरी) गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पं.अमर नाथ पाण्डेय
वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय

समस्त जनपद व देश वासियों को (26 जनवरी) गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रहमत फाउंडेशन–जगदीशपुर अमेठी

वन दरोगा की सह पर बेखौफ ठेकेदार ने काटे दो हरे आम के पेड़

वसीम अहमद

जगदीशपुर,अमेठी।दबंग ठेकेदारों की मर्जी के आगे नहीं चलती पुलिस व वन विभाग की जहां एक तरफ प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है।वहीं दूसरी तरफ लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा भरपूर फायदा लिया जा रहा है।आचार संहिता का जी हां हम बात कर रहे हैं अमेठी जिला के तहसील मुसाफिरखाना क्षेत्र के जगदीशपुर थानाक्षेत्र के केशवदास का पुरवा की जहां वन माफियाओं के द्वारा दो आम के हरे पेड़ काटे गए।अगर यही हाल रहा तो क्षेत्र को रेगिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की माने तो दबंग लकड़ी के ठेकेदारों का है बोलबाला प्रशासन व वन विभाग की खाउ कमाउ नीति के चलते हो रहे हैं बड़े पैमाने पर कार्य जहां आए दिन ट्रकों से भर कर लकड़ी बाहर देशों में भेजी जाती है इस पर नहीं पड़ती किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नजर क्षेत्र में आए दिन कहीं ना कहीं लकड़हारे का आरा चलता ही रहता है।जिसमे स्थानीय वन दरोगा व अलावा वनकर्मी चंद पैसे की खातिर बिना परमिट पेड़ कटवाने में जरा सा भी नही हिचकते।ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी जिम्मेदार के कान पर जू नही रेंगती अतवारा में क्षेत्र की कटाई लकड़ी को ट्रकों पर लादा गया लेकिन जिमेदार तो मूक दर्शक है।कभी कभार खानापूर्ति के नाम पर दो पेड़ की जगह एक का जुर्माना कर खानापूर्ति कर लेते है।वहीं जब इस सम्बंध में पत्रकार वन दरोगा से जानकारी लेने का प्रयास करते है।तो वह गाली गलौज कर अभद्रता पर उतारू हो जाते है।वहीं इस मामले में जिला वन अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में नही है मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी।

लोकतंत्र के उत्सव में भागी बनेंगे 100 पार 359 बुजुर्ग मतदाता

महराजगंज। लोकतंत्र के उत्सव को लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में जज्बा कायम है। इस बार 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 359 बुजुर्ग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य विधाता बनेंगे। ये मतदाता आजादी से लेकर हर चुनाव में मतदान कर अपने हौंसले के जरिये नई पीढ़ी को मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश देते हैं। बुजुर्ग मतदाता को मतदान के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन जुटा है। बुजुर्ग मतदाता को बैलेट मत से वोट करने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग मतदाता बूथ पर आकर ही मतदान करना चाहता है, तो उन्हें बूथ तक आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मतदान मित्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। बुजुर्ग मतदाता को ससम्मान केंद्र के पास बैठने की व्यवस्था होगी। मतदान मित्र उन्हें घर से लेकर मतदान कराएंगे और घर तक पहुंचाएंगे। आजादी के बाद से अब तक डाले वोट पनियरा विधानसभा क्षेत्र के गनेशपुर के टोला तुलसीपुर निवासी हरिहर शुक्ल ने बताया कि 1951 में आजाद भारत में सबसे पहले मत का प्रयोग किया था। हमेशा शिक्षित, ईमानदार और किसानों के हित को समझने वाले को वोट दिया। आप सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में बिना किसी लालच के निर्भीक होकर मतदान करें। धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना, सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस बार भी अपने मताधिकार का प्रयोग करुंगा। पनियरा विधानसभा क्षेत्र के पनियरा गांव निवासी पारसनाथ जायसवाल ने बताया कि पहली बार 1951 में मतदान का अवसर मिला था। इसके बाद से हमेशा मतदान करने जाता हूं और घर के सदस्यों को भी ले जाता हूं। वोट के बिना विकास संभव नहीं है। संविधान ने हमें अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार दिया है। इस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान आवश्यक है। पहले और वर्तमान के चुनाव में अब काफी अंतर है। गांवों में भोपू से प्रचार होता था, लेकिन धीरे–धीरे समय के साथ काफी बदलाव आ गया है।

चुनाव ड्यूटी में शिथिलता क्षम्य नहीं : डीएम

महराजगंज। डीएम सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के एनआइसी में मतदानकार्मिकों के ड्यूटी से संबंधित प्रथम चरण का रैंडमाइजेशन किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। प्रथम चरण के रेंडमाइजेशन में जिले के पोर्टल पर पर फीड सभी चुनावकार्मिकों में से उन चुनावकार्मिकों का चयन किया गया, जिनकी ड्यूटी मतदानकर्मी के रूप में लगाई जाएगी। अभी इन कर्मियों को विधानसभा का आवंटन नहीं हुआ है। द्वितीय चरण के रेंडमाइजेशन में इनकी नियुक्ति विधानसभावार किया जाएगा। डीएम ने कहा कि द्वितीय चरण के ट्रेनिग के पहले सभी चयनित मतदानकार्मिकों को बूस्टर डोज लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव एक अत्यंत

महत्वपूर्ण व संवेदनशील विषय है। इसलिए सभी चुनावकर्मी पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जनपद में 2221 बूथों के लिए कुल 9784 कर्मियों को मतदान के लिए लगाया जाएगा। इस दौरान सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम डा. पंकज कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। निर्वाचन ड्यूटी का आदेश प्राप्त कर लें महराजगंजरू मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया कि 27 जनवरी को किसी अधीनस्थ द्वारा प्रातरू 10रू00 बजे विकास भवन के कक्ष संख्या नौ में से अपने कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों का निर्वाचन ड्यूटी आदेश प्राप्त कर लें। उसी दिवस में निर्वाचन ड्यूटी आदेश संबंधित अधिकारी को प्राप्त कराकर, उसकी प्राप्ति रसीद उपलब्ध करा दी जाए। मास्टर ट्रेनरों को मतदान कराने का बताया गया तरीका विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनरों को कलेक्ट्रेट सभागार में द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें ईवीएम से मतदान कराने का तरीका सहित चुनाव के विभिन्न गाइडलाइन की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा सभी मास्टर ट्रेनर ईवीएम व चुनाव से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पहलू को अच्छी तरह समझ लें, ताकि मतदान कार्मिकों के सभी शंकाओं को दूर कर सकें। मतदान की सफलता सबसे अधिक आपके द्वारा दिए गए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पर निर्भर करेगा। इस दौरान जिला विकास अधिकार जगदीश त्रिपाठी, पीडी राजकरन पाल समेत प्रशिक्षु मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।

महराजगंज में 102 मिले कोरोना संक्रमित, चिंता बढ़ी

महराजगंज।जिले में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रत्येक दिन नये संक्रमित पाए जा रहे हैं। मंगलवार को अब तक का सर्वाधिक 102 संक्रमित पाए गए हैं। इस प्रकार सक्रिय रोगियों की संख्या 393 तक पहुंच गई है। लगातार संक्रमितों के बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। सदर, घुघली, परतावल, पनियरा, निचलौल, फरेंदा, नौतनवा आदि क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा संबंधित मोहल्लों और गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सतर्कता भी बरती जा रही है। नोडल अधिकारी डा. आइए अंसारी ने बताया कि जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 13353 है। इसमें 12814 रोगियों ने कोरोना से जंग जीत ली है। अब तक 142 की मृत्यु हो चुकी है। दो रोगी अस्पताल में भर्ती है। जबकि अन्य होम क्वारंटाइन है, जिनकी स्वास्थ्य टीम निगरानी कर रही है। 2879 की हुई कोरोना जांच महराजगंजरू जिले में मंगलवार को कुल 2879 लोगों की कोरोना की जांच गई। इसमें एंटीजन से 1562 लोगों की जांच की गई है, जबकि आरटीपीसीआर जांच के लिए 1317 लोगों का नमूना भेजा गया है। नोडल अधिकारी डा. आइए अंसारी ने बताया कि बृजमनगंज में 220, धानी में 120, घुघली में 122, लक्ष्मीपुर में 192, महराजगंज में 102, मिठौरा में 191, नौतनवा में 600, निचलौल में 348,

पनियरा में 115, परतावल में 400, फरेंदा में 94, सिसवा में 153 तथा महिला अस्पताल में 222 लोगों की जांच की गई है। महराजगंजरू जिले में कोरोना से बचाव का टीका लगवाने को लेकर मंगलवार को लोगों में काफी उत्साह रहा। इस दौरान कुल 19980 लोगों को टीका लगाया गया। जिला महिला अस्पताल, सीएचसी सहित निर्धारित स्थलों पर टीका के लिए किशोर, युवक, महिलाएं और पुरुषों की भीड़ लगी रही। उधर गांवों में स्वास्थ्य टीम घर–घर भ्रमण कर टीका लगाने में जुटी रही। नोडल अधिकारी डा. आइए अंसारी ने बताया कि कुल 19980 लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका अवश्य लगवाएं। यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

निर्भीक होकर करें मतदान, लोकतंत्र की यही पहचान

महराजगंज। जिले के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान जहां कई विद्यालयों में आज छात्र, छात्राओं ने मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए रंगोली बनाए, वहीं मेहंदी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलायी गयी। डीएम सत्येन्द्र कुमार ने पं. दीन दयाल उपाध्याय इंटर में लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। विद्यालय की छात्राओं द्वारा बनाए गए रंगोली का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें। किसी के प्रलोभन में न आए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर मतदाता को मतदान करना आवश्यक है। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक विजय बहादुर सिंह, दुर्गेश कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल ने विकास भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों को शपथ दिलाई। जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्राचार्य डा. दिग्विजय नाथ पांडेय ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान के तर्ज पर मतदान किया जाना चाहिए। मुख्य नियंता राहुल कुमार सिंह, डा. प्रशांत पांडेय, डा.अक्षय कुमार, डा. मिथलेश चौधरी, छटठू यादव, डा. शांति शरण मिश्र, डा. विनय कुमार खरबार, विधिनारायण यादव, शमशाद अहमद, नरेंद्र नाथ सिंह, आदित्य मद्धेशिया आदि उपस्थित रहे। दिग्विजय नाथ इंटरमीडिएट कालेज चौक बाजार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डा. हरिन्द्र यादव ने एनसीसी के कैडेट्स, स्काउट गाइड के स्काउट और गाइड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं को कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराते हुए मतदान तथा मतदान जागरूकता के लिए शपथ दिलाया गया।

जनपद न्यायाधीश ने मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाई

गोरखपुर । जनपद में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे उत्साह के साथ गुरू गोरक्षनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने मतदाताओं को बिना प्रलोभन, भय एवं निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर उनके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरन आनंद भी मौजूद रहे।कार्यक्रम में 10 नये मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किया गया तथा लगभग 20 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की गयी। इसके अतिरिक्त निर्वाचक अग्रदूतों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया, यह अग्रदूत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संकेत मुकबधिर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गीत एवं नृत्य के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया गया।इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि मतदान लोकतंत्र में पुनीत कर्तव्य है। निर्वाचन में भागीदारी बढ़ाने के लिए ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की महती भूमिका होती है एंव समाज हित में तथा देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखने के लिए जुड़ने हेतु मताधिकार का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और उसमें मताधिकार का प्रयोग करने हेतु शक्ति प्रदत्त है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी मतदाताओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निर्वाचन एक महायज्ञ की भांति होता है, हर मतदाता की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर करें, मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे रैम्प, पेयजल, विद्युत, शौचालय आदि की गयी है। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि इस कार्य में सभी मतदाताओं का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बूथों पर कोविड–19 से बचाव हेतु सेनेटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था रहेगी, कोविड प्रोटोकाल का पालन अवश्य किया जाये।

आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सजग

गोरखपुर। रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल, गोरखपुर को 22 जनवरी, 2022 को गोरखपुर जं. स्टेषन पर गष्त के दौरान 11 वर्ष की एक लड़की लावारिस हालत में मिली। पूछताछ के उपरान्त लड़की को चाइल्ड लाइन, गोरखपुर को सुपुर्द किया गया। रेलवे सुरक्षा बल, गोरखपुर को 22 जनवरी, 2022 को गोरखपुर जं. स्टेषन पर गाड़ी सं. 15273 के आगमन पर 17 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला। पूछताछ के उपरान्त लड़के को चाइल्ड लाइन, गोरखपुर को सुपुर्द किया गया। 22 जनवरी, 2022 को गाड़ी सं. 12555 में रेलवे सुरक्षा बल स्कोर्ट पार्टी को 17 वर्ष की एक लड़की लावारिस हालत में मिली। पूछताछ के उपरान्त लड़की को चाइल्ड लाइन, लखनऊ को सुपुर्द कर दिया गया। 22 जनवरी, 2022 को बुढ़वल रेलवे स्टेषन के प्लेटफार्म सं. 01 पर 03 माह की एक बच्ची को उसकी मां गाड़ी सं. 15204 में छोड़कर जा रही थी। रेलवे सुरक्षा बल, बुढ़वल द्वारा त्वरित कार्यवाही कर बच्ची को गाड़ी से उतारकर बच्ची व उसकी मां को चाईल्ड लाइन, बाराबंकी को सुपुर्द कर दिया गया। 23 जनवरी, 2022 को एकमा स्टेषन के प्लेटफार्म सं. 01 पर रेलवे सुरक्षा बल गष्त के दौरान 17 वर्ष की एक लड़की लावारिस हालत में मिली। पूछताछ के उपरान्त लड़की को चाइल्ड लाइन, छपरा को सुपुर्द किया गया। 23 जनवरी, 2022 को गाड़ी सं. 19038 में रेलवे सुरक्षा बल स्कोर्ट पार्टी को 07 वर्ष की एक लड़की लावारिस हालत में मिली। पूछताछ के उपरान्त लड़की को चाइल्ड लाइन, गोण्डा को सुपुर्द कर दिया गया।

रेलवे का बड़ा निर्णय, सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर समायोजति होंगे लोको पायलट

गोरखपुर, संवाददाता। सहायक स्टेशन मास्टर के अभाव में ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं होगा। मालगाड़ियां भी निर्बाध चलती रहेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक लोको पायलट (एएलपी) अब रिक्त चल रहे सहायक स्टेशन मास्टर (एएसएम) के 200 तथा वाराणसी मंडल के 50 गार्ड (ट्रेन मैनेजर) की जिम्मेदारी संभालेंगे। रनिंग स्टाफ की कमी के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने पदों को समायोजित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) को पत्र लिखा है। दिशा–निर्देश के क्रम में रेलवे प्रशासन ने समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी और इज्जतनगर मंडल में ही लखनऊ लगभग 200 सहायक स्टेशन मास्टर के पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर पूर्व (वाराणसी मंडल) में 15 सहित वाराणसी मंडल में गार्डों के करीब 50 पद रिक्त हैं। जबकि, पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक लोको पायलटों की संख्या निर्धारित से 15 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018–19 में रेलवे प्रशासन ने एक हजार की जगह करीब 1600 पदों पर सहायक लोको पायलटों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली। पूर्वोत्तर रेलवे के एक हजार पदों पर भर्ती तो हो गई लेकिन लगभग 600 अभ्यर्थियों को दूसरे जोन में भेजना पड़ा।कुछ अभ्यर्थी अभी भी दूसरे जोन की परिक्रमा कर रहे हैं। यही नहीं विभागीय पदोन्नति के माध्यम से परीक्षा पास करने वाले मुख्यालय गोरखपुर के करीब 150 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभी भी सहायक लोको पायलट बनने के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। रिक्त पदों के अंतर को बराबर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सहायक स्टेशन मास्टर तथा गार्ड के रिक्त पदों पर सहायक लोको पायलटों को समायोजित करने का अहम निर्णय लिया है। बोर्ड के इस निर्णय से सहायक स्टेशन मास्टर और गार्ड के रिक्त पद तो भर ही जाएंगे, तैनाती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी सहायक लोको पायलट बनने का अवसर मिल जाएगा। जानकारों के अनुसार गार्डों की कमी के चलते वाराणसी मंडल के छपरा और नरकटियागंज रूट पर मालगाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं। स्टेशनों पर दस घंटे की ड्यूटी पूरी होने पर गार्ड ट्रेन को छोड़कर उतर जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन को गार्डों की व्यवस्था करनी पड़ रही है।एनई रेलवे मजदूर यूनियन नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता ने बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस व्यवस्था से रेलकर्मी तो समायोजित होंगे ही, ट्रेनों का संचालन भी निर्बाध होगा। उन्होंने रेलवे प्रशासन से इस व्यवस्था को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की है।वाराणसी मंडल ने गार्ड के रिक्त के सापेक्ष 15 प्रतिशत पदों पर चतुर्थ श्रेणी (ट्रैक मेंटेनर) के कर्मचारियों से भरने का निर्णय लिया है। इसके लिए वाराणसी स्थित रेलवे के प्रशिक्षण स्कूल में 27 से 31 जनवरी तक परीक्षा आयोजित होगी।

कैसे हुई गीता प्रेस की स्थापना, लागत से 60 फीसद कम मूल्य पर कैसे बिकती हैं यहां की किताबें

गोरखपुर, । भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और जन–जन तक पहुंचाने का जो अभियान सेठजी जयदयाल गोयंदका ने 1922 में कलकत्ता (कोलकाता) से शुरू किया, उसके स्थायी साधन के रूप में 23 अप्रैल 1923 को गोरखपुर में गीताप्रेस की स्थापना हुई। आज जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो ऐसे में आजादी के पूर्व स्थापित गीताप्रेस व संस्कृति के संरक्षण व प्रचार में उसकी भूमिका पर चर्चा मौजूं हो जाती है। अपनी स्थापना से लेकर आज तक गीताप्रेस 88.24 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। इसमें 1558 लाख प्रतियां केवल गीता की हैं।गीताप्रेस 15 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित कर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सदाचार की संस्कृति को जन–जन तक पहुंचाने में संलग्न है। हर व्यक्ति को पुस्तकें सुलभ हो सकें, इसके लिए यहां प्रकाशित पुस्तकें लागत मूल्य से 30 से 60 प्रतिशत कम मूल्य पर पाठकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इतना ही नहीं गीताप्रेस का पूरा माहौल हमारी संस्कृति को बल देता है। वहां फोन करने जब तक फोन रिसीव नहीं होता, नारायण–नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ती है। दीवारों पर पूरी गीता खुदी हुई है। वहां के कर्मचारियों में भी धर्म व संस्कृति का पूरा समावेश है। उनका मानना है कि वे भगवान का कार्य कर रहे हैं, जो लोक कल्याणकारी है। यही नहीं यह प्रेस धर्म–संस्कृति का संवर्धन

करते हुए एक हजार से अधिक लोगों की आजीविका भी चलाता है।आमजन को कम मूल्य पर गीता उपलब्ध हो सके, इसके लिए कलकत्ता में सेठजी जयदयाल गोयंदका ने गीता छपवानी शुरू की। उसमें अशुद्धियां होने पर सुधार के लिए जब पुनरू प्रेस में भेजा तो प्रेस मालिक ने कहा कि इतनी शुद्ध गीता छपवानी है तो अपना प्रेस लगा लीजिए। कोलकाता के सत्संग में जयदयाल गोयंदका की मुलाकात गोरखपुर के घनश्याम दास जालान व महावीर प्रसाद पोद्दार से हुई। उन्होंने कहा कि यदि प्रेस गोरखपुर में लगे तो हम उसे संभाल लेंगे। इसके बाद यहां उर्दू बाजार में 23 अप्रैल 1923 को 10 रुपये किराए पर एक कमरा लेकर प्रेस स्थापित किया गया। उस समय 600 रुपये में हैंड प्रेस प्रिंटिंग मशीन मंगाई गई और गीता की छपाई शुरू हो गई। अगस्त 1926 में साहबगंज के पास 10 हजार रुपये में एक मकान खरीदा गया। आज वहीं गीताप्रेस स्थित है। आज प्रेस के पास दो लाख वर्ग फीट जमीन है। इसमें 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस, कार्यालय व मशीनें हैं। 55 हजार वर्ग फीट में दुकानें व आवास हैं।गीताप्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 17 अप्रैल 1965 को सेठजी के शरीर त्याग के बाद गीताप्रेस की बागडोर संभाल ली। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन करते हुए उनकी टीका भी लिखी है, ताकि पाठकों को आसानी से पुस्तकें समझ में आ जाए। 22 मार्च 1971 को वह भी गोलोकवासी हो गए। इस समय पूरी व्यवस्था ट्रस्टी देवीदयाल अग्रवाल देख रहे हैं।गीताप्रेस का मुख्य द्वार हमारी संस्कृति का ध्वजवाहक है। द्वार के सभी हिस्सों में भारतीय संस्कृति, धर्म एवं कला की गरिमा को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके निर्माण में देश की गौरवमयी प्राचीन कलाओं तथा विख्यात मंदिरों से प्रेरणा लेते हुए उनकी निर्माण शैलियों का आंशिक रूप में शामिल किया गया है। इसके निर्माण में अजंता के चौत्य व विहार, एलोरा के कैलास मंदिर, कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर, काशी के विश्वनाथ व अन्नपूर्णा मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर के ड्क्षलगराज मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के कंडरिया महादेव मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप, आबू के जैन तीर्थ, उज्जैन के महाकाल मंदिर, केदारनाथ, गया के बौद्ध मंदिर, जनकपुर के जानकी मंदिर आदि की कला का आश्रय लिया गया है।गीताप्रेस की पुस्तकें लागत मूल्य से कम में बेची जाती हैं। इसका घाटा पूरा करने के लिए प्रेस ने हरिद्वार में आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री लगाई है। साथ ही गीताप्रेस भवन में उसकी अपनी दुकान के अलावा कई दुकानें हैं, जो किराये पर दी गई हैं। इनसे होने वाली आय से प्रेस का घाटा पूरा किया जाता है।सनातन धर्म की पुस्तकें व आर्ष ग्रंथ हमारी संस्कृति के आधार हैं। 15 भाषाओं में इनका प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा लुप्तप्राय कर्मकांड व संस्कारों की पुस्तकों का भी प्रकाशन हो रहा है। उनमें शास्त्रों का प्रमाण देते हुए संस्कारों की पद्धतियों का विवेचन किया गया है।

सम्पादकीय

शहादत की ज्योति

पिछली आधी सदी से इंडिया गेट पर प्रज्वलित 'अमर जवान ज्योति' हर देशवासी को राष्ट्र की बलिदानी गाथा से जोड़ती रही है। अमर जवान ज्योति 26 जनवरी, 1972 को अस्तित्व में आई थी, जिसे वर्ष 1971 के भारत–पाक युद्ध में शहीद जवानों की स्मृति में प्रज्वलित किया गया था। वहीं 25 फरवरी, 2019 को इसके निकट ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन हुआ, जहां आजाद भारत में शहीद हुए पच्चीस हजार से अधिक

जवानों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, जिनकी याद में वहां भी अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। मोदी सरकार ने दोनों ज्योतियों के विलय के बारे में फैसला लिया था और देश के महानायक नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जन्मशती को इस मौके के रूप में चुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और ऐतिहासिक गलती सुधारने की बात कही। साथ उन असंख्य बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया जो त्याग और बलिदान के बावजूद चर्चाओं में न आ सके। दरअसल, इंडिया गेट 1921 में प्रथम विश्व युद्ध तथा तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था। सत्ता पक्ष के लोग जहां इसे साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक मानते रहे हैं वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि आजादी से पहले भारतीय सैनिकों के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अतीत को लेकर एक समग्र दृष्टि की जरूरत है। बहरहाल, देश में एक समग्र राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की कमी जरूर पूरी हुई है जो देश के बहादुर शहीद सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का ही पर्याय है। इसका निर्माण भी नई दिल्ली में विकसित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में इंडिया गेट के पास ही किया गया है जहां अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रज्वलित ज्योति में हुआ है। निस्संदेह, कृतज्ञ राष्ट्र अपने शहीदों के बलिदान से कभी उऋण नहीं हो सकता है। उनके बलिदान की अखंड ज्योति हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी कि देश ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिये कितनी बड़ी कीमत चुकायी है। बहरहाल, यह तार्किक ही है कि शहादत को समर्पित ज्योति को दिल्ली में एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए। हालांकि, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की अमिट स्मृतियां भारतीय जनमानस के दिलो–दिमाग में सदैव ही रही हैं। इस मार्ग से गुजरते लोगों का ध्यान बरबस इस ओर सम्मान से चला ही जाता था। वहीं सरकार व सेना का मानना रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ही वह एकमात्र स्थान हो सकता है जहां शहीदों को गरिमामय सम्मान मिल सकता है। दूसरी ओर, इंडिया गेट क्षेत्र में छत्र के नीचे जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा लगायी गई है, वहां कभी इंग्लैंड के पूर्व राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। निस्संदेह स्वतंत्र भारत में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता था। माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण स्थान में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा का लगाया जाना, उनके अकथनीय योगदान का सम्मान ही है।

अदालत की मंशा स्थाई व्यवस्था बने

अनूप भटनागर

राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 1985 में देश में पहली बार बनाया गया दल बदल कानून विवादों के निपटारे में अत्यधिक विलंब की वजह से अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। दसवीं अनुसूची के तहत बने इस कानून के अभी तक के अनुभव और दल बदल के खिलाफ याचिकाओं के निपटारे के मामले में अध्यक्षों की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में अब इसमें व्यापक संशोधन करने और ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थाई न्यायाधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सदन का अध्यक्ष भी चूंकि राजनीतिक दल का ही सदस्य होता है, इसलिए दल बदल संबंधी विवादों के निष्पादन में निष्पक्षता की कमी महसूस होती है। इस बाबत शीर्ष अदालत ने दो साल पहले सुझाव दिया था कि संसद को दसवीं अनुसूची के तहत ऐसे विवादों के निपटारे की जिम्मेदारी अर्द्ध न्यायाधिकरण के रूप में अध्यक्षों को सौंपने के प्रावधान पर नये सिरे से विचार करना चाहिए। इसकी एक प्रमुख वजह दल बदल करने वाले सांसदों और विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बने कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होने की वजह से अध्यक्ष द्वारा ऐसे मामलों में फैसला करने में अत्यधिक विलंब भी है। इस संबंध में तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर सहित अनेक विधान सभा अध्यक्षों के समक्ष लंबित ऐसे मामलों का उदाहरण दिया जा सकता है। राज्यों की विधान सभाओं में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए मूल राजनीतिक दल की याचिकाओं पर निपटारे में अत्यधिक विलंब की वजह से कई बार ये मामले सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में ही एक मामले में दल बदल कानून के तहत लंबित याचिकाओं के निपटारे के लिए समय सीमा और दिशा–निर्देश प्रतिपादित करने से इंकार कर दिया था। न्यायालय का स्पष्ट मत था कि यह काम संसद का है और उसे ही इस पर विचार करना होगा। यही नहीं, कर्नाटक विधान सभा में हुए दल

बदल से संबंधित मामले में 2019 में शीर्ष अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सदन का अध्यक्ष अगर तटस्थ रहने का संवैधानिक दायित्व नहीं निभा सकता है तो वह इस पद के योग्य नहीं है। संसद और विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की आया राम–गया राम की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1985 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया था। इस कानून में हालांकि, कुछ संशोधन भी किए गए लेकिन इसके बाद भी सदन में पाला बदलने वाले सांसदों और विधायकों के बारे निर्णय का अधिकार पूरी तरह से अध्यक्ष के पास ही था। ऐसे मामलों के निपटारे में हो रहे विलंब का ही नतीजा था कि 21 जनवरी, 2020 को सर्वोच्च अदालत ने सुझाव दिया कि संसद को दल बदल कानून के तहत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए संविधान में संशोधन करके एक स्थाई न्यायाधिकरण की स्थापना करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। न्यायालय का विचार था कि संसद को दल बदल करने वाले सदस्य के मामले में फैसला करने का अधिकार एक अर्द्ध–न्यायाधिकरण के रूप में अध्यक्ष को सौंपने संबंधी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल, ऐसे विवाद का निपटारा करते समय भी अध्यक्ष एक राजनीतिक दल विशेष का ही सदस्य होता है। इसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए न्यायाधिकरण का अध्यक्ष शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाने का प्रावधान किया जा सकता है। दरअसल, आज जहां दल बदल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले में फैसला होने में अत्यधिक समय लग रहा है तो दूसरी ओर दल बदल कानून की मार से बचने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि सदन के कार्यकाल के अंतिम साल में चुनाव नजदीक आने पर पाला बदलने का रास्ता अपना रहे हैं। चुनावी साल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देकर दूसरे दल में शामिल होने की इस बीमारी से हालिया दिनों में सभी दल पीड़ित हैं। अक्सर ऐसी गतिविधियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। सरकार अगर वास्तव में दल बदल जैसी समस्या पर अंकुश पाना चाहती है तो उसे कानून में यह प्रावधान करने पर विचार करना चाहिए कि चुनावी साल में सदन और मूल राजनीतिक दल से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति कम से कम एक साल तक किसी अन्य राजनीतिक दल का प्रत्याशी बनने के अयोग्य होगा। यह सर्वविदित है कि न्यायिक हस्तक्षेप से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्वच्छता, पारदर्शिता और पवित्रता बनाये रखने और इससे संदिग्ध छवि वाले व्यक्तियों को बाहर रखने में काफी सफलता मिली है। उम्मीद है कि सरकार सर्वोच्च अदालत के सुझावों पर और समय गंवाए बगैर ही उचित कदम उठायेगी।

गुणवत्ता की मुफ्त शिक्षा का वादा करें दल

भरत झुनझुनवाला

चुनाव के इस माहौल में मुफ्त बांटने के वादे करने की होड़ मची हुई है। कोई साड़ी बांटता है, कोई साइकिल, कोई लैपटॉप और कोई मुफ्त में बस यात्रा। यहां तक कि कहीं तो शराब भी मुफ्त बांटने की बात की जा रही है। कुछ मतदाता मानते हैं कि कम से कम जनता को 5 साल में एक बार ही सही, कुछ तो हासिल हो। सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियां लागू कर जनता के रोजगार और धंधे को पस्त कर दिया है इसलिए मुफ्त में जो मिले कुछ लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन विचारणीय यह है कि मुफ्त क्या बांटा जाए? ऐसे में यदि सच्ची अंग्रेजी शिक्षा को ही मुफ्त बांट दीजिए तो जनता भी सुखी हो जाएगी और पार्टी को संभवतरू जीत भी हासिल हो जाए? कहावत है कि किसी व्यक्ति को मछली देने के स्थान पर मछली पकड़ना सिखाना ज्यादा उत्तम है क्योंकि यदि मछली पकड़ना सीख लेगा तो वह आजीवन अपनी आय अर्जित कर सकता है। इसी प्रकार यदि हम युवाओं को मुफ्त साइकिल और लैपटॉप वितरित करने के स्थान पर यदि मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा दें तो वे साइकिल और लैपटॉप स्वयं खरीद लेंगे और आजीवन अपनी जीविका भी चला सकेंगे। जनता में अंग्रेजी शिक्षा की गहरी मांग है। शहरों में घरों में काम करने वाली सहायिकाओं द्वारा भी अपने बच्चों को 1,500 से 2,000 रुपए प्रतिमाह की फीस देकर अच्छी अंग्रेजी के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजने का प्रयास किया जाता है। वे अपनी आय का लगभग तिहाई हिस्सा बच्चों की फीस देने में व्यय कर देती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि शिक्षा की मांग है लेकिन अच्छी शिक्षा खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। दिल्ली की आप सरकार ने सरकारी शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं लेकिन इसके बावजूद सरकारी विद्यालयों के हाई स्कूल में 72 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जबकि प्राइवेट स्कूलों में 93 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दूसरे राज्यों में सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत अधिक दुरूह है जबकि इन पर सरकार द्वारा भारी खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रति छात्र 25,000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जा रहे थे। वर्तमान वर्ष 2021–22 में यह रकम लगभग 30,000 रुपये हो गई होगी। इसमें भी सरकारी विद्यालयों में तमाम दाखिले फर्जी किए जा रहे हैं। बिहार के एक अध्ययन में 9 जिलों में 4.3 लाख फर्जी विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में पाए गए। इन फर्जी दाखिलों को दिखाकर स्कूल के कर्मचारी मध्यान्ह भोजन और यूनिफॉर्म इत्यादि की रकम को हड़प जाते हैं। किसी अन्य आकलन के अभाव में हम मान सकते हैं कि 20 प्रतिशत विद्यार्थी फर्जी दाखिले के माध्यम से दिखाए जाते होंगे। इन्हें काट दें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति सच्चे विद्यार्थी पर 37,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च किया जा रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत बच्चे वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं। अतः यदि इस 37,000 रुपये प्रति सच्चे छात्र की रकम को प्रदेश के सभी छात्रों यानी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल दोनों में पढ़ने वाले छात्रों में वितरित किया जाए तो प्रत्येक छात्र पर उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 20,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च रही है। चुनाव के समय पार्टियां वादा कर सकती हैं कि इस 20,000 रुपये की रकम में से 12,000 रुपये प्रदेश के सभी छात्रों को मुफ्त वाउचर के रूप में दे दिये जाएंगे। इस वाउचर के माध्यम से वे अपने मनचाहे विद्यालय में फीस अदा कर सकेंगे। यह 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र सरकारी शिक्षकों के वेतन में से सीधे कटौती करके किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सरकारी अध्यापकों का वेतन वास्तव में कम हो जाएगा। वे अपने विद्यालय को आकर्षक बना कर पर्याप्त संख्या में छात्रों को आकर्षित करेंगे तो वे अपने वेतन में हुई इस कटौती की भरपाई वाउचर से मिली रकम से कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में तमाम विश्वविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं। इन कोर्सों में छात्र द्वारा भारी फीस दी जाती है, जिससे पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतन का पेमेंट किया जाता है। इसी तर्ज पर सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, छात्रों को आकर्षित कर उनके वाउचर हासिल कर अपने वेतन की भरपाई कर सकते हैं। ऐसा करने से सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों को लाभ होगा। सरकारी विद्यालयों के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वे अपनी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं, जिससे कि वे पर्याप्त संख्या में छात्रों को आकर्षित कर सकें, उनके वाउचर हासिल कर सकें और अपने वेतन में हुई कटौती की भरपाई कर सकें।

बीए की छात्रा को दरिंदगी के बाद मार डाला

प्रयागराज,। संवाददाता। शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई। कर्नलगंज के बघाड़ा इलाके में 18 वर्षीय बीए की छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए कातिलों ने शव को कुएं में फेंक दिया था। तीन दिन पहले छात्रा अपने प्रेमी अमन के साथ बघाड़ा के निर्जन इलाके में घूमने गई थी। जहां उन दोनों को साथ देख बिगड़ैल युवकों ने हमला कर दिया। प्रेमी को पीटकर छात्रा को जंगल में उठा ले गए थे। फिर दरिंदगी के बाद छात्रा को मारकर लाश कुएं में फेंक दी। सोमवार आधी रात पुलिस ने छात्रा का शव गहरे कुएं से निकाला। पुलिस प्रेमी समेत कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।सरायममरेज थाना क्षेत्र के जंघई इलाके में रहने वाला एक शख्स गुजरात में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी बड़ी बेटी ईश्वर शरण डिग्री कालेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वह सलोरी स्थित एक लाज में गांव की एक लड़की के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। छात्रा का प्रेमी अमन भी उसी कालेज में पढ़ता और सलोरी में किराए पर रहता है। वह मूलरूप से आजमगढ़ का रहने वाला है। बताया जाता है कि तीन दिन पहले शाम करीब साढ़े सात बजे छात्रा अपने रूममेट को दवा व कापी लेने की बात कहकर निकली और वापस नहीं आई। मोबाइल भी बंद हो गया। अगले दिन प्रेमी ने फोन करके पूछा तो उसे छात्रा के कमरे पर न आने का पता चला।तब रूममेट ने छात्रा के घरवालों को सूचना दी। स्वजन परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचकर तहरीर, जिसके आधार पर गुमशुदगी का केस लिखा गया। जांच के दौरान पुलिस को अमन के बारे में पता चला तो उसे उठाकर कड़ाई से पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि वह छात्रा के साथ बघाड़ा के जंगल की ओर गया था। जहां उसका कुछ युवकों से विवाद हुआ। विरोध पर उन्होंने उसके साथ ही छात्रा को पीटने लगे। तब वह जान बचाकर भाग निकला, जिसके बाद अपराधिक प्रवृत्ति के युवक छात्रा को जंगल में उठा ले गए थे। मगर उसने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। फिर घरवालों ने अमन के खिलाफ हत्या के इरादे से अपहरण का केस दर्ज कराया।प्रथम दृष्टया प्रेमी की भूमिका संदिग्ध है। उसे और उसके कुछ साथियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो सकेगी।

दोस्तों ने घर से बुलाकर कर दिया कत्ल, प्रयागराज में सड़क किनारे मिला ठेकेदार के पुत्र का शव

प्रयागराज, संवाददाता। शहर में मुट्ठीगंज के सालिकगंज मंडी के रहने वाले ठेकेदार नरेंद्र जायसवाल के पुत्र राहुल (20) की हत्या कर दी गई। उसके शव को रविवार देर रात थरवई थानांतर्गत मनसैता नदी के समीप सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया गया। मृतक के परिवार के लोगों का आरोप है कि उसके चार दोस्तों से विवाद था और रविवार शाम वही उसे घर से बुलाकर ले गए थे। मुट्ठीगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपितों के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिले। तलाश में छापेमारी की जा रही है।सालिकगंज मंडी निवासी नरेंद्र जायसवाल ठेकेदार हैं। उनके दो पुत्रों में छोटा राहुल उनके साथ रहता था। रविवार शाम करीब पांच बजे वह घर में था। उसी समय किसी ने उसे आवाज दी, वह घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। घरवाले उसकी तलाश में लगे रहे। सोमवार अपराह्न घरवालों को जानकारी मिली कि थरवई क्षेत्र में किसी युवक की लाश मिली है। वह थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने बताया कि सुबह मनसैता नदी के पास सड़क किनारे गड्ढे में युवक की लाश मिली थी। उसकी पहचान न होने के कारण लावारिस में शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया गया है।पुलिसकर्मियों ने बरामद शव की फोटो दिखाई तो घरवालों ने बताया कि लाश राहुल की थी। वह रोने–बिलखने लगे। पुलिस ने तहरीर देने को कहा, जिस पर उन्होंने मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा लिखाने की बात कही। देर शाम मृतक के बड़े भाई रजत जायसवाल ने पुलिस को तहरीर दी।

सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा पूर्व अपने केन्द्रों का भ्रमण करें : डीएम

प्रयागराज(संवाददाता)। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी)–2021 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सेण्ट एन्थोनी गर्ल्स इ.का में केन्द्र व्यवस्थापकों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक की। जिसमें उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को परीक्षा पूर्व अपने–अपने केन्द्रों पर भ्रमण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रथम पाली में 183 परीक्षा केन्द्रों पर 84017 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे तथा द्वितीय पाली में 132 परीक्षा केन्द्रों पर 59895 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा को नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए प्रथम पाली में सभी 183 केन्द्र व्यवस्थापकों को अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज ने सम्बोधित करते हुए आवश्यक जानकारी एवं दिशा निर्देश दिये। द्वितीय पाली में सभी 63 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज के संयोजकत्व में हुई।

जिलाधिकारी ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों से कहा कि परीक्षा सम्पन्न कराना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है।

शासन की मंशानुसार जिला प्रशासन परीक्षा सकुशल सम्पन्न कराने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, सचल दस्ते निरस्तर भ्रमणशील रहेंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। परीक्षा कार्य में जिसे जो भी दायित्व आवंटित किया गया, उसके प्रति पूरी तरह सजग रहें। सभी परीक्षा केन्द्रों पर कोविड हेल्प–डेस्क की अनिवार्य रूप से स्थापना की जाय। मास्क, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, सेनेटाइजर की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षा कार्य में लगे किसी भी अधिकारी–कर्मचारी के पास एन्ड्रॉयड मोबाइल नहीं रहेगा, मात्र केन्द्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट कैमरा रहित की पैड वाला मोबाइल प्रयोग कर सकेंगे। सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 गज तक धारा 144 लागू रहेगी। अपर जिलाधिकारी (नगर) ने सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को बताया कि परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जाय। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर वीडियोग्राफी होगी। प्रश्न पत्रों को खोले जाने एवं परीक्षा समाप्ति पर सीलिंग–पैकिंग की भी वीडियोग्राफी करायी जायेगी। सभी केन्द्रों पर सीसीटीवी से अनवरत निगरानी की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सभी केन्द्रों में ऐसा कक्षा जिसमें परीक्षा नहीं है उन्हें सीलबंद रखा जायेगा। ऐसे केन्द्र व्यवस्थापक जिनके पास कक्ष निरीक्षकों की कमी हो वे तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे, उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे। परीक्षा की शुचिता बनी रहे इसके प्रति सभी सजग व सचेष्ट रहेंगे।

प्रयागराज की सोरांव विधानसभा सीट अपना दल का गढ़

2017 में भाजपा ने 21 वर्ष बाद जीत का स्वाद चखा

प्रयागराज(संवाददाता)। सोरांव (सुरक्षित) विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आती है। 2017 में सोरांव (सुरक्षित) में भाजपा समर्थित अपना दल (एस) के जमुना प्रसाद ने बहुजन समाज पार्टी के गीता देवी को 17735 वोटों से हराया था। यहां से भाजपा ने गठबंधन में 21 साल बाद जीत का स्वाद चखा। इस सीट पर सभी दल के प्रत्याशी जीत चुके हैं, लेकिन अब यह क्षेत्र अपना दल का गढ़ माना जाता है।

सीट की मुख्य बातें

सोरांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पासी मतदाता हैं। इस सीट पर कांग्रेस, जनता पार्टी और दो बार जनता दल का कब्जा रहा है। 1985 में कांग्रेस के भोला सिंह यहां से जीते थे। 1989 में भी वे यहां से जीते, लेकिन इस बार वे जनता दल के उम्मीदवार थे। उन्होंने राम मंदिर की लहर के दौर में भी तीसरी बार 1991 में जीत दर्ज की। लेकिन 1993 में बहुजन समाज पार्टी के हीरामणि पटेल बाजी मार ले गए। 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत मिली और रंग बहादुर पटेल कमल खिलाने में कामयाब रहे। लेकिन 2002 में बसपा के मोहम्मद मुज्तबा सिद्दिकी ने उन्हें हरा दिया। 2007 में सिद्दीकी दूसरी बार यहां से जीते। 2012 में परिसीमन के बाद यह सीट सुरक्षित हो गई और समाजवादी पार्टी के सत्यवीर मुन्ना जीत दर्ज करने में सफल रहे। 2017 में इस सीट पर भाजपा गठबंधन–अपना दल (एस) का कब्जा हो गया।

चुनाव पर एक नजर

वर्ष 1974 में इस सीट पर भारतीय क्रांति दल से जंग बहादुर सिंह पटेल जीते थे। जंग बहादुर पुनः 1977 में भी जनता पार्टी के बैनरतले जीते। 1980 में राधे श्याम पटेल जनता पार्टी एससी से जीते। इसके बाद भोला सिंह 1985 में कांग्रेस से, 1989 में जनता दल एवं 1991 में पुनः जनता दल से चुनाव जीते। 1993 में बसपा ने खाता खोला और हीरा मणि पटेल जीत कर आए। 1996 में भाजपा का खाता खुला और रंग बहादुर पटेल ने जीत दर्ज की। लेकिन 2002 में बसपा से मो. मुजतबा सिद्दीकी ने जीत दर्ज कर पुनः कब्जा कर लिया और 2007 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। 2012 में यहां सत्यवीर मुन्ना ने जीत दर्ज कर सपा का खाता खोला। लेकिन 2017 में अपना दल एस से डॉ जमुना प्रसाद सरोज ने जीत दर्ज की। वर्ष 2017 के चुनाव में यहां मतदाताओं की संख्या 3,60,205 थी। अब आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 18,007 बढ़ कर 3,78,212 हो गयी है। जो आगामी चुनाव में अपना विधायक चुनेंगे।

राजनीतिक इतिहास

आजादी के बाद से सोरांव विधानसभा सीट का नाम चार बार बदला है। वहीं इस विधानसभा सीट पर सभी दल के प्रत्याशियों को जीत का मौका मिला है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से 9 पर जीत मिली। यह भाजपा की बड़ी कामयाबी रही। अब 2022 के चुनाव में दोबारा जीत दर्ज करना किसी चुनौती से कम नहीं है।

हावड़ा की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां अब प्रभावित नहीं होगी

प्रयागराज, (संवाददाता)। प्रयागराज छिवकी–नैनी खंड के 1.45 किमी. सेक्शन पर तीसरी लाइन को नैनी स्टेशन के मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ इंटरलॉक करने का कार्य 17 जनवरी को पूरा कर लिया गया है। इस कार्य के साथ रूट की संख्या 82 से बढ़कर 87 हो गई है। इसके लिए नैनी यार्ड का रिमॉडलिंग किया गया। जिसमें 3 डायमंड क्रासिंग हटाकर 12 क्रॉस ओवर जोड़े गए। जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अब नैनी जंक्शन के डाउन लूप लाइन में खड़ी गाड़ी छिवकी के डाउन लूप लाइन में सीधे जा सकेगी जिससे डाउन मेन लाइन से चलने वाली गाड़ियां प्रभावित नहीं होंगी। अप मेन लाइन से सीधे एक्सटेंडेड लूप लाइन में गाड़ी को रखा जा सकेगा। इससे पीछे आने वाली अपलाइन की मेल एक्सप्रेस गाड़ियां प्रभावित नहीं होंगी। डायमंड प्वाइंट हट जाने से पॉइंट मेंटेनेंस आसान हो गया है, जिससे पॉइंट फेल होने की सम्भावना कम हो गई है। अप एंड डाउन लाइन में टी.डब्ल्यू.एस टर्नआउट लग जाने से रेलगाड़ियों की एवरेज स्पीड में बढ़ोतरी होगी। इस कार्य से इस खंड पर चलने वाली मेल–एक्सप्रेस ट्रेनों के समय पालन में सुधार आएगा। इस व्यस्ततम खंड पर तीसरी लाइन की आवश्यकता काफी पहले से महसूस की जा रही थी जिसे इस वर्ष माघ मेला के प्रारम्भ में ही पूरा कर लिया गया। सिग्नल विभाग द्वारा किए गए उपर्युक्त सराहनीय इंटरलॉकिंग कार्य से रेलगाड़ियों के समय पालन में काफी सुधार आएगा तथा मालगाड़ियों के एवरेज स्पीड में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने छोड़ा हाथ, हुए बीजेपी के साथ

(एजेन्सी)

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में आरपीएन सिंहन बीजेपी में शामिल हुए। आरपीएन सिंह के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सहारनपुर में जिला अध्यक्ष रह चुके शशि वालिया ने बीजेपी का दामन थामा हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश सचिव और नोएडा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र अवाना भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले आरपीएन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूं। कयास लगाया जा रहा है कि आरपीएन सिंह बीजेपी से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आरपीएन सिंह ने आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे त्यागपत्र की प्रति ट्विटर पर साझा की और कहा, "आज, जब पूरा राष्ट्र गणतन्त्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद।" उन्होंने इस्तीफे में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा है, "मैं राष्ट्र, लोगों और पार्टी की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका (सोनिया का) धन्यवाद करता हूं।" आरपीएन सिंह कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। आरपीएन सिंह केंद्र में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली संप्रग सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। वह 2009–2014 तक उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट से सांसद रहे। इससे पहले वह कई वर्षों तक पडरौना विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि भाजपा आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से चुनावी मैदान में

उतार सकती है। पडरौना आरपीएन सिंह का परंपरागत क्षेत्र रहा है। 2009 में वह पडरौना लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था।

आरपीएन सिंह कांग्रेस के लिए झारखंड के प्रभारी भी रह चुके हैं। आरपीएन सिंह के समर्थकों का दावा है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें लगातार दरकिनार किया जा रहा था और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी।

स्वामी प्रसाद मौर्य से जब आरपीएन सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पडरौना से चुनाव लड़ने की बात कही गई तो वह बोले कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आरपीएन को पडरौना से हरा देगा।

असेम्बली इलेक्शनः शाह कैराना के बाद जाएंगे मथुरा

लखनऊ,संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचे हुए हैं।विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए सभी नेता एड़ी–चोटी का जोर लगा रहे है। सभी पार्टी के नेता अपनी पार्टी की उपलब्धियों के साथ–साथ जनता से भी रूबरू हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर बैन लगा दिया है,जिसकी वजह से बीजेपी अब जनसम्पर्क और घर–घर जाकर जनता से रूबरू हो रही हैं।बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 27 जनवरी को मथुरा जाएंगे और वहां पर पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। 26 जनवरी के बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता यूपी समेत चुनावी राज्यों में प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से घर–घर जाकर चुनाव प्रचार किया था।कैराना में अमित शाह ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से हिंदूओं के पलायन का मुद्दा बड़ी जोरशोर से उठाया था,जिसके बाद अब शाह कैराना के मथुरा भी जाएंगे।अमित शाह मथुरा के साथ ही गौतमबुद्ध नगर नोएडा भी चुनाव प्रचार करेंगे। वही केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में जनता से मुलाकात करेंगे। डोर टू डोर प्रचार करेंगे।अमित शाह के मथुरा जाने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं,क्योंकि बीजेपी के चुनाव एजेंडे में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा है और भाजपा किसी भी कीमत ये दांव खेलने से बाजा नहीं आएगी। वेस्ट यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली थी,क्योंकि वेस्ट में मुस्लिम आबादी खासी संख्या में है और उसके बावजूद बीजेपी इस इलाके में सीटें जीतने में पूरी तरह से कामयाब रही थी । भाजपा को इस बार भी बड़ी जीत की उम्मीद है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुक्सान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष इसी रणनीति के तहत भाजपा के खिलाफ दांव खेलने वाला है। यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 312 सीट अकेले जीत चुकी है जबकि सहयोगी दलों के साथ बीजेपी गठबंधन 325 सीटें जीती थी।

पुरानी पेंशन बहाली पर टिकट देकर जबाब दें सपा प्रमुख : परिषद

लखनऊ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए शीघ्र ही मतदान शुरू होने वाला है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए किए जा रहे कुर्तकों का जबाब देने के लिए सपा प्रमुख को अपनी घोषणा सच साबित करने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि को टिकट की घोषणा करनी चाहिए। प्रदेश भर के कर्मचारियों की मांगों पर खुलकर बोलने वाला कमचारी समाज के बीच से होने पर भ्रांतियों का तत्काल निदान होगा। इसके लिए सदन में कर्मचारी प्रतिनिधित्व जरूरी है। जिसके लिए समाजवादी पार्टी को कर्मचारी संगठनों के प्रत्याशियों की अविलम्ब घोषणा करनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली और आउट सोर्सिंग के मुद्दे पर लगभग दस वर्षो से आन्दोलनरत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं ने आगामी चुनाव में कर्मचारी शिक्षक और उनके परिजनों के शतप्रतिशत मतदान की ब्लॉक स्तर तक कार्ययोजना तैयार की है। परिषद के घटक संघों, परिसंघों, एसोसिएशन के ब्लांक स्तर तक के पदाधिकारियों को योजना से अवगत कराते हुए उस दल के पक्ष में मतदान का संकल्प कराया गया है जो दल पुरानी पेंशन बहाली और आउटसोर्सिंग शोषण का शिकार कार्मिको शोषण से मुकित दिलायेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने आज पत्रकारों से बॉतचीत में स्पष्ट किया कि कोई भी सरकार आसानी से पुरानी पेंशन बिना किसी वित्तीय भार के कर सकती है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों श्री अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली के स्पष्ट रूप से घोषणा कर चुके है। उन्होंने कहाकि उनकी घोषणा के बाद कर्मचारियों और शिक्षकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। ऐसे में गुमराह करने वाले स्वंयभू नेताओं को जबाब देने के लिए पार्टी को कर्मचारी और शिक्षकों में विश्वास दिलाने के लिए एक दो कर्मचारी शिक्षक नेताओं को विधानसभा में ले जाने की अतिशीघ्र घोषणा कर कर्मचारी शिक्षकों के बीच दोमुंही राजनीति करने वालों को करारा जबाद देना चाहिए।उक्त नेताओ ने कहाकि प्रेस कान्फैंस कर सार्वजनिक रूप से पुरानी पेंशन बहाली और आउट सोर्सिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ऐतिहासिक ऐलान ही नही किया बल्कि स्पष्ट रूप से इसे घोषणा पत्र में शामिल करने का ऐलान किया है। इसके बावजूद अगर विरोध स्वरूप अनर्गल प्रलाप किये जा रहे है तो इसका जबाब देने के लिए समाजवादी पार्टी को तत्काल पुरानी पेंशन बहाली और आउट सोर्सिंग के लिए काम कर रहे कर्मचारी शिक्षक संवर्ग के दो चार नेताओं को अपनी पार्टी से विधानसभा में ले जाने का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ऐसे ही पुरानी पेंशन का ऐलान नही किया, बल्कि इसके लिए दो से तीन माह का मंथन, आर्थिक विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त आलानौकरशाहों की राय ली गई है। उन्होंने सामान्य उदाहरण देते हुए बताया कि कोई भी शासकीय सेवक अपने सेवाकाल में 300 से 360 महीने सेवारत रहता है। हर महिने पेंशनमद में उस कार्मिक और सरकार का एक निश्चित अंशदान जमा होता है। इतने माहो के बाद उस कर्मचारी के खाते में सामान्यतः इतनी राशि जमा हो जाती है कि उसके ब्याज से पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इसका जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन देने से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है।

सपा के टिकट पर मुबारकपुर से लड़ सकते हैं गुड्डू जमाली

लखनऊ,संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दो बार आजमगढ़ की मुबारकपुर से विधायक रह चुके शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आज बसपा से इस्तीफा दे दिया। उनकी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हुई मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई कि वह आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन इस बीच आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी को शाह आलम गुड्डू जमाली ने ज्वाइन नहीं किया। इस बीच बसपा ने मुस्लिम चेहरे के तौर पर पूर्व विधायक अब्दुस सलाम को मैदान में उतार दिया। इन सब बातो से यह लगने लगा कि शायद समाजवादी पार्टी मुबारकपुर विधानसभा सीट से मुस्लिम चेहरे को मैदान में ना उतारे लेकिन विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर में शाह आलम गुड्डू जमाली पिछले 10 वर्षों में एक मजबूत जनप्रतिनिधि के तौर पर उभरे हैं और इनको जन समर्थन भी काफी मिलता रहा है इन सब चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुड्डू जमाली की मुलाकात हुई और गुड्डू जमाली ने इस बात को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मुबारकपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। वह चुनाव की तैयारियों में विधिवत रूप से जुड़ गए हैं लेकिन अभी आजमगढ़ की किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है ना ही समाजवादी पार्टी की ओर से मुबारकपुर सीट पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के प्रत्याशी बनाए जाने की अधिकारी पुष्टि की गई है, लेकिन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है ।उनका कहना है कि वह अगला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुबारकपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे और उनको जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है ।भारी मतों से जीत कर वह विधानसभा जाएंगे और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की बनेगी।

रोहित शर्मा की वापसी पर कौन होगा बाहर, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में किसे मिलेगा मौका?

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया को वनडे सीरीज में 0–3 से क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। चोट के कारण नियमित कप्तान रोहित शर्मा दौरे पर नहीं जा सके थे। ऐसे में शिखर धवन के साथ ओपनिंग करते दिखाई दे सकते हैं। शिखर ने अफ्रीका दौरे पर अच्छी बल्लेबाजी की। तीन मैचों में दो अर्धशतक लगाए। ऐसे में राहुल मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते

केएल राहुल के हाथों में टीम इंडिया की कमान थी। अब टीम इंडिया को घरेलू सरजमीं पर वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे और टी–20 सीरीज खेलनी है। सीरीज की शुरुआत छह फरवरी से होगी। पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी। सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी तय मानी जा रही है। ऐसे में उनकी वापसी पर टीम से कौन बाहर होगा? यह एक बड़ा सवाल है।रोहित के न रहते हुए शिखर धवन और केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका में ओपनिंग की। टीम इंडिया के कप्तान की वापसी के बाद वह दिख सकते हैं। ऐसे में श्रेयस अय्यर और रिषभ पंत में से किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ सकता है। इसका कारण है कि राहुल कीपिंग भी कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में ज्यादा से ज्यादा युवा खिलाड़ियों को मौका देने के बारे में भी सोच सकता है। ऐसे में विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव को ज्यादा मौका नहीं मिला है। मिडिल आर्डर को मजबूत बनाने के लिए दोनों को लगातार मौका देना जरूरी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्रा चहल और भुवनेश्वर कुमार की टीम से छुट्टी हो सकती है। अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में इनका प्रदर्शन काफी खराब रहा। भुवनेश्वर की जगह दीपक चाहर को नियमित तौर पर मौका मिलने की संभवना है। गेंदबाजी के साथ–साथ वह बल्लेबाजी में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा फिट होने पर रवींद्र जडेजा की भी वापसी होगी। वाशिंग्टन सुंदर और अक्षर पटेल भी एक विक्लप हैं। वर्क लोड मैनेजमेंट की बात करें तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए यह काफी जरूरी है। वह तीनों फार्मेट में खेलते हैं। ऐसे में उन्हें आराम दिया जाना लगभग तय है। उनकी गैरमौजूदगी में टीम में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों को खेलने का मौका मिल सकता है।वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन वनडे और इतने ही टी–20 मैचों की मेजबानी क्रमशरू अहमदाबाद और कोलकाता करेंगे।बीसीसीआइ ने शनिवार को यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि कोविड–19 महामारी के मद्देनजर यात्रा को कम करने के लिए स्थानों की संख्या को कम किया गया है। अहमदाबाद में छह, नौ और 11 फरवरी को पहला, दूसरा और तीसरा वनडे और फिर 16, 18 और 20 फरवरी को कोलकाता में पहला, दूसरा और तीसरा टी–20 मैच होगा। वेस्टइंडीज दौरे के बाद भारत को श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में टी–20 सीरीज खेलनी है।

कोहली के कप्तानी छोड़ने पर लोग काफी कुछ बोल चुके हैं, इस गपशप में पड़ना मेरा काम नहीं

मस्कट। टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि विराट कोहली का जवाब है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने यह

बात कही है।समाचार एजेंसी एएनआइ से शास्त्री ने कहा, श्कई लोग पहले ही विराट कोहली और उनके कप्तानी छोड़ने पर काफी कुछ कह चुके हैं। मेरे पास गपशप करने और इसके विस्तार में आने का समय नहीं है। मैंने खेल से सात साल बाद ब्रेक लिया। मैं टीम का हिस्सा रहा हूं और मैं बहुत स्पष्ट हूं, कि मैं सार्वजनिक रूप कुछ भी खराब नहीं बोलूंगा। टीम से अलग होने के बाद सबकुछ खत्म। मैं अपने किसी भी खिलाड़ी के बारे में सार्वजनिक मंचों पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस पर बहुत स्पष्ट हूं।दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारने पर टीम इंडिया टीम के बारे में बात करते हुए शास्त्री ने कहा, श्स्टैंडर कैसे नीचे जा सकता है? आप पांच–साल तक नंबर एक टेस्ट टीम रहे हैं। कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कोहली के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बारे में लोग पहले ही काफी कुछ बोल चुके हैं और इस गपशप में पड़ना उनका काम नहीं है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद कोहली ने टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया था। इससे पहले टी–20 से कप्तानी छोड़ने के बाद वनडे की कप्तानी से उन्हें हटा दिया गया था। कोहली के अचानक से टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद हर कोई आश्चर्य में रह गया था। इसके कारण तरह–तरह की बातें होने लगीं।कहा जाने लगा कि बीसीसीआइ और कोहली के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। उनपर कप्तानी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। इसका एक कारण दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के सवाल पर

बैंक निजीकरण पर होगी नई घोषणा, बजट में बैंकों को वित्तीय मदद की उम्मीद कम

नई दिल्ली। मई, 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार के लिए यह पहला साल ऐसा होगा जब देश के बैंकग सेक्टर की स्थिति अच्छी दिख रही है। कोरोना के बावजूद सरकारी बैंकों का मुनाफा पिछली तीन तिमाहियों से लगातार बढ़ रहा है, फंसे कर्ज (एनपीए) की स्थिति काफी हद तक काबू में दिखाई दे रही है, कर्ज वितरण की रफ्तार भी बढ़ने के संकेत हैं और नई तकनीक अपनाने की वजह से लागत भी घटने के संकेत है। ऐसे में आम बजट 2022–23 में भारतीय बैंकग सेक्टर को खास वित्तीय मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन बैंक निजीकरण को आगे बढ़ाने को लेकर लेकर केंद्र सरकार और खुलकर सामने आ सकती है। तैयारी यह भी है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण का एक पूरा रोडमैप भी पेश किया जाए और इसके लिए आवश्यक कानूनों में संशोधन की रूप–रेखा भी सामने रखा जाए।पिछले आम बजट में दो बैंकों और बीमा कंपनी के निजीकरण करने की घोषणा करने के बावजूद सरकार उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है।बैंकिंग उद्योग के सूत्रों का कहना है कि सरकारी बैंकों या बीमा कंपनियों के निजीकरण के काम को सरकार इस कैलेंडर वर्ष के दौरान ही पूरा करना चाहेगी। अप्रैल–मई, 2024 में आम चुनाव से ठीक पहले सरकार विपक्ष को बैंक व बीमा निजीकरण का मुद्दा नहीं देना चाहेगी। यह लगभग तय है कि हर साल बजट से सरकारी बैंकों को मिलने वाली राशि इस बार नहीं दी जाएगी। यह भी संभव है कि बैंकग सेक्टर में बड़े कारपोरेट घरानों के प्रवेश को लेकर भी सरकार बजट में कोई नीतिगत स्पष्टता लाने की कोशिश करे। इस बारे में नीतिगत स्पष्टता नहीं होने की वजह से ही बैंक निजीकरण की राह आसान नहीं हो पा रही।बैंकों की तरफ से भी वित्त मंत्री के समक्ष अपनी मांगों की सूची सौंपी जा चुकी है।बैंकों की एक प्रमुख मांग यह है कि पिछले कुछ वर्षों से जमा दरों का आकर्षण काफी तेजी से खत्म हुआ है। बाजार में नए निवेश विकल्प आने की वजह से आगे भी जमा आकर्षित करना आसान नहीं होगा। ऐसे में बैंकग जमा को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाने चाहिए तथा होम लोन पर कर छूट के लिए देय ब्याज दर की मौजूदा सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाई जानी चाहिए।

क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से हिसाब चुकाना चाहेगी टीम इंडिया, 2020 फाइनल में मिली थी हार

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे आइसीसी अंडर–19 क्रिकेट विश्व कप का सुपर लीग स्टेज यानी क्वार्टरफाइनल 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस दिन इंग्लैंड की टीम सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। सबकी नजरें 29 जनवरी को भारत और बांग्लादेश वाले मुकाबले पर होंगी। इसका कारण है साल 2020 विश्व कप। टीम इंडिया को तीन विकेट से हराकर बांग्लादेश की टीम चौंपियन बनी थी। ऐसे में यश धुल की कप्तानी वाली टीम इस हार का बदलना लेना चाहेगी। चार बार के चौंपियन भारत ने ग्रुप बी में अपने तीनों मैच जीतकर शानदार फार्म में सुपर लीग चरणों में प्रवेश किया। राज बावा और अंगक्रिश रघुवंशी के बड़े शतकों की मदद से भारत ने युगांडा पर 326 रन की विशाल अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। टीम ने दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड को हराया।टीम इंडिया ने भले ही लीग स्टेज के अपने तीनों मैचों को जीत लिया हो, लेकिन उसकी राह में चुनौती कम नहीं थी। आयरलैंड के खिलाफ मैच से पहले कप्तान और उपकप्तान समेत पांच खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित हो गए। इससे जैसे–तैसे 11 खिलाड़ियों को उतार पाई। कप्तान यश धुल, उप

कप्तान शेख रशीद के अलावा आराध्य यादव, वासु वत्स, मानव परख और सिद्धार्थ यादव संक्रमित हो गए थे। इसके बाद भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया।गत विजेता बांग्लादेश की राह क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने आसान नहीं रहा। इंग्लैंड से अपना पहला मैच हारने के बाद ग्रुप ए में टीम दूसरे स्थान पर रही। टीम ने कनाडा को आठ विकेट हराया। इसके बाद बारिश प्रभावित मैच में यूएई को नौ विकेट (डकवर्थ–लुईस नियम) से हराया।आइसीसी अंडर–19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के फाइनल मैच में टीम इंडिया को तीन विकेट से बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

तिल के लड्डू खाने के बेहतरीन फायदे

तिल फाइबर, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा–6 फैटी एसिड, मैगनीज, विटामिन ई व एंटी–ऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। इसके साथ ही इसकी तासीर गर्म होने से सर्दियों में तिल खाना फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से हड्डियों में मजबूती आने के साथ दिल व दिमाग हेल्दी रहता है। ऐसे में बॉलीवुड फिटनेस एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तिल के लड्डू की तस्वीर शेयर करके इसे खाने की सलाह दी है। चलिए जानते हैं तिल के लड्डू खाने के फायदे...

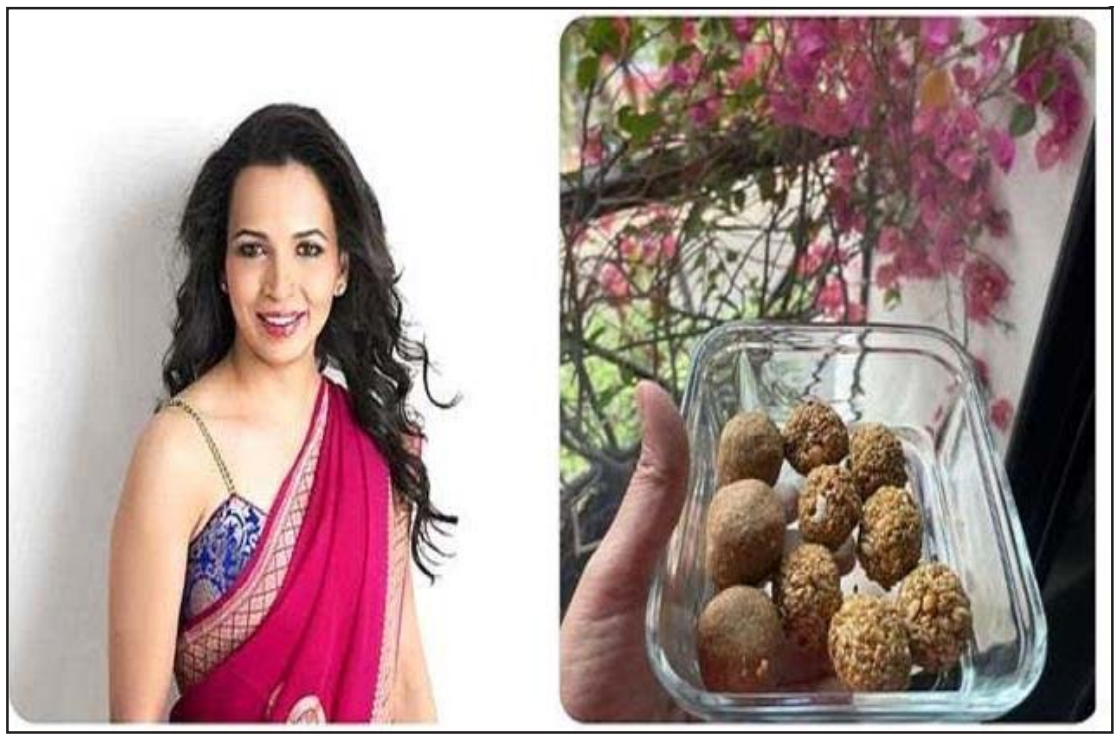

कोलेस्ट्रोल रहेगा कंट्रोल

तिल के लड्डू खाने से शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल कम होने में मदद मिलती है। ऐसे में दिल स्वस्थ रहने के साथ इससे जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा कम रहेगा।

ऊर्जा बढ़ाएं

इसमें हाई फैट कंटेंट होने से शरीर को अप्रत्याशित ऊर्जा मिलने में मदद मिलती है। ऐसे में थकान, कमजोरी दूर होकर दिनभर तरोताजा महसूस होता है।

दिमाग रहेगा हेल्दी

तिल में पोलिअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा–6 जैसे अच्छे फैट्स पाएं जाते हैं। ऐसे में इससे तैयार लड्डूओं का सेवन करने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है।

संक्रमण से रहेगा बचाव

इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे में शरीर का संक्रमण से बचाव रहता है।

हड्डियां होंगी मजबूत

काले तिल में कैल्शियम और जिंक अधिक मात्रा में होता है। ऐसे में इसका सेवन करने से मांसपेशियों व हड्डियों में मजबूती आती है।

ब्लड प्रेशर और शुगर रखें कंट्रोल

तिल में मैग्नीनियम भरपूर मात्रा में होता है। इसतरह इसका सेवन करने से शरीर में इन्सुलिन और ग्लुकोज लेवल कंट्रोल रहता है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है।

पाचन तंत्र होगा मजबूत

तिल में डाइटरी फाइबर्स होने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं होने से बचाव रहता है।

अच्छे मूड बनाने में मददगार

तिल में टाइरोसिन नामक अमीनो एसिड

पाया जाता है जो सेरोटोनिन से जुड़ा होता है। इसके सेवन से शरीर में अच्छे मूड सेल्स बनते हैं।

स्किन व बालों के लिए फायदेमंद

सेहत नहीं, स्किन व बालों को हेल्दी रखने में भी तिल मदद करता है।

इससे तैयार लड्डू का सेवन करने से त्वचा

व बालों से जुड़ी समस्याओं से बचाव रहता है।

शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहती हैं हरनाज संधू

जब से पंजाब की मशहूर मॉडल हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, वह चर्चा में हैं। आए दिन उनसे जुड़ीं जानकारियां सामने आ रही हैं और फैंस भी हरनाज की हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं।

यह तो सभी जानते हैं कि हरनाज को एक्टिंग का शौक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह बॉलीवुड के किस एक्टर संग काम करना चाहती हैं?हरनाज से पूछा कि वह बॉलीवुड में किस अभिनेता संग डेब्यू करना चाहती हैं तो उन्होंने कहा, मैं शाहरुख खान का बहुत सम्मान करती हूं। जितनी मेहनत उन्होंने की है और अब भी कर रहे हैं, वह कोई नहीं कर सकता। फिर भी वह जमीन से जुड़े हुए हैं और सफल हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह शाहरुख हर इंटरव्यू में बात करते हैं, वह मुझे प्रेरित करता है। वह बेहतरीन कलाकार होने के साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। हरनाज ने यह भी बताया कि वह किस निर्देशक की फिल्म में काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, अगर मौका मिला तो मैं संजय लीला भंसाली के साथ जरूर काम करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे उनकी फिल्में पसंद हैं। उन्होंने कहा, उनकी फिल्मों की चॅलिटी, आर्ट और गहराई बेहद अच्छी होती है। मैं भंसाली की भव्य फिल्मों से काफी प्रभावित हूं। बता दें कि श्रद्धा कपूर जैसी कई अभिनेत्रियां भंसाली के साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। हरनाज ने कहा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं कभी अपनी जिंदगी में कोई योजना नहीं बनाती, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं बॉलीवुड का हिस्सा बनना चाहूंगी, क्योंकि यह मेरा सपना है। उन्होंने कहा, अभिनय मेरा पेशा है। मैं लगभग पांच साल तक थिएटर कर चुकी हूं। मैं लोगों की उस दकियानूसी सोच को तोडना चाहती हूं, जो सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकतीं। फिल्मों के जरिए आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं।

डाइजेशन सुधारे कब्ज भगाए, आप भी नहीं जानते होंगे छुहारे खाने के ये फायदे

सर्दियों से बचने की बात करें तो दिमाग में ड्राई–फ्रूट दिमाग ख्याल आता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर को गर्माहट भी देते हैं। हम भी आज आपको ड्राई फ्रूट्स में से एक सूखा छुआरा खाने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खजूर को सुखाकर छुहारे बनाए जाते हैं जो एनर्जी बूस्टर, विटामिन और खनिजों का पावरहाउस हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि छुहारा खाने से सेहत को क्या–क्या फायदे मिलते हैं।

एक दिन में कितने छुहारे खाने चाहिए

एक्सपर्ट के अनुसार, हर दिन 2–3 से ज्यादा छुहारा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है इसलिए ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है।

बेहतर पाचन क्रिया

छुहारा खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और आप कब्ज, एसिडीटी जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं। आप इसे दूध में उबालकर भी पी सकते हैं।

सर्दियों में फायदेमंद

सर्दियों में छुहारे वाला दूध पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और शरीर को गर्माहट भी मिलती है। इससे आप सर्दी–जुकाम, खांसी, गले में खराश जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं।

पीरियड्स दर्द से आराम

छुहारे कैल्शियम और विटामिन सी का बढ़िया स्त्रोत है। पीरियड्स में छुहारे वाला दूध पीने से पेट की ऐठंन, कमर व पीठ दर्द से आराम मिलता है।

शुगर क्रेविंग में फायदेमंद

डायबिटीज मरीज मीठेपन की क्रेविंग को दूर करने के लिए छुहारा खा सकते हैं। इससे ग्लूकोज में शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा।

ब्रेन के लिए फायदेमंद

फाइबर से भरपूर छुहारे का सेवन ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। इससे याददाश्त बढ़ती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है।

स्टेमिना बढ़ाए

सेक्सुअल स्टेमिना बढाने में भी छुहारा बहुत फायदेमंद माना जाता है। छुहारे , इलायची को दूध में उबाल। इसे छानकर शहद मिलाकर खाली पेट पीएं। इससे आपको फर्क नजर आएगा।

हार्ट अटैक से बचाव

शोध के अनुसार, छुहारे में पोटैशियम होता है, जो हार्ट अटैक का जोखिम कम करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और खून के थक्के बनने की संभावना भी कम होती है।

पूर्वांचल युग
स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक, संजय कुमार गुप्ता द्वारा ग्राम व पोस्ट श्यामदेउरवा थाना महाराजगंज साईं फ्लैक्स पटेल तिराहा बैकुण्डपुर महाराजगंज से प्रकाशित
संपादक
संजय कुमार गुप्ता
मो0 नं0 8418938089
नोट : समाचार पत्र से सम्बन्धित सारे वाद विवाद महाराजगंज न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगें।
Email: purvanchalyug@gmail.com
website-www.purvanchalyug.com